सरकार सोने पर घटाए आयात शुल्क

राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के प्रयास में लगी सरकार सोने के बढ़ते आयात से लगातार परेशान है। इस कीमती धातु में लोगों का रुझान बांटने के लिए सरकार ने हाल ही में आयात शुल्क बढ़ाने की भी घोषणा की। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को बजट में सोने को लेकर कुछ निश्चित तथा उद्योग की दृष्टि से हितकर कदम उठाने चाहिए।

पृथ्वीराज कोठारी

रिद्धीसिद्धी बुलियंस लिमिटेड के निदेशक पृथ्वीराज कोठारी का कहना है कि सरकार ने हाल ही में सोने पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 4 से 6 फीसदी करने का कदम उठाया है। इस तरह के कदम से सोने की घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी अंतर हो गया है। इसका नतीजा यह है कि तस्करी के जरिए लाए जाने वाले सोने की मात्रा में वृद्धि हुई है। यह कदम निपुण कारीगरों के रोजगार पर भी संकट का कारण बनेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बजट में इस विषय पर जरूर गंभीरता दिखाएगी और शुल्क का कोई नियमित ढांचा निर्मित हो सकेगा। आभूषणों पर हॉलमार्किंग का प्रावधान सभी के लिए एक अच्छा कदम है। इसके अधिक से अधिक और बेहतर कार्यान्वयन के लिए सरकार को हॉलमार्किंग सेंटर्स की स्थापना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्राफा उद्योग के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी बहुत जरूरी है। भारत में बहुत सी खानें हैं लेकिन कमजोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण हम उनका बहुत छोटा सा हिस्सा ही प्रयोग कर पाने में समर्थ हो पाए हैं। वहीं दूसरी ओर चीन ने अपने यहां वित्तीय और बुनियादी प्रोत्साहनों तथा एकल खिड़की व्यवस्था के जरिए सर्राफा उद्योग को तेजी से बढ़ाने का काम किया है। आरएंडडी के मामले में एफडीआई एक सहायक कदम हो सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार को जीएसटी लागू करने की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ाना चाहिए।

बच्छराज बामलवा

अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण व्यापार परिसंघ (जीजेएफ) के चेयरमैन बच्छराज बामलवा का कहना है कि सोने पर आयात शुल्क मौजूदा छह फीसदी से कम कर 2 फीसदी किए जाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि शुल्क में वृद्धि से भले ही वैध तरीके से आयात कम दिख रहा है लेकिन इससे तस्करी बढ़ी है और उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है आयात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पीली धातु की मांग पर अंकुश लगाने के लिए सोने में निवेश से जुड़े ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) तथा म्यूचुअल फंड जैसे निवेश के साधनों पर प्रतिभूति कर बढ़ाया जाना चाहिए। आभूषण के आयात पर भी शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए ताकि कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में अंतर न हो। उन्होंने कहा कि सोने के आयात में कमी लाने के लिए सरकार को घरों में निष्क्रिय पड़े सोने के भंडार को बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहन योजना पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि निष्क्रिय पड़े सोने को बाहर निकालने के लिए सरकार स्वैच्छिक उद्घोषणा योजना ला सकती है। इस तरीके से बाहर आने वाले सोने को रिजर्व बैंक अपने पास निश्चित अवधि जैसे तीन से पांच साल तक रखे और संबंधित ग्राहक को इसके एवज में कुछ ब्याज दे। यह कदम आयात घटाने में सहायक हो सकता है।